

पीएम मोदी 1500 से ज्यादा स्थानों पर करेंगे युवाओं से संवाद

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को देशभर में 1,500 से अधिक स्थानों पर युवाओं और खिलाड़ियों से वार्चुअल संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम खेल मंत्रालय के 'खेलो इंडिया संवाद-खेल की बात, प्रधानमंत्री के साथ' अभियान के तहत आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम 29 अगस्त को होने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस से दो दिन पहले होगा। 29 अगस्त को हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। इसी दिन देश में राष्ट्रीय खेल दिवस



मनाया जाता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अगस्त को राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात कर चुके हैं। इस बार युवाओं और खिलाड़ियों के साथ उनका संवाद वार्चुअल माध्यम से होगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कार्यक्रम चार से पांच स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली भी शामिल है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसूख मांडविया यहां आयोजित कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

खास-खबरें

एसी कोच में चूहे ने बुजुर्ग की नाक काटी

नईदुनिया ब्यूरो, इंदौर: ऊना-इंदौर एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में रविवार रात सो रहे 78 वर्षीय सेवानिवृत्त अधिकारी की नाक पर चूहे ने काट लिया। चूहे के काटने से उनकी नाक से खून आने लगा, जिसके बाद कोच में हड़कप मच गया। इंदौर पहुंचने पर परिजन बुजुर्ग को कोकिलाबेन अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें रेबीज का पहला टीका लगाया। परिजनों के अनुसार, ट्रेन में सफर शुरू होने के कुछ समय बाद ही कोच में चूहा दिखाई देने लगा था। उन्होंने इसकी जानकारी रेलवे कर्मचारियों को दी और कोच में गंदगी की शिकायत भी की। कर्मचारियों ने सफाई तो कर दी, लेकिन चूहे रोकने के लिए कीटनाशक नियंत्रण की कार्रवाई नहीं की गई।

नावालिग से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप

नईदुनिया ब्यूरो, नर्मदापुरम:पचमढी में 17 वर्षीय नावालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने स्थानीय जिप्सी चालक हरिओम और उसके साथ होटल में काम करने वाले पवन बंसल व अभिषेक वंशकार को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, 19 अगस्त को छात्रा का स्कूल का दोस्त उससे मिलने पचमढी आया था। बस स्टैंड पर दोनों की मुलाकात जिप्सी चालक से हुई। आरोप है कि तीनों छात्रा और उसके दोस्त को जंगल में ले गए। वहां छात्रा के दोस्त को जिप्सी से बांधकर छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। बाद में दोनों को बस स्टैंड पर छोड़ दिया गया और किसी को घटना बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई।

सीजेपी 5 सितंबर को फिर सड़कों पर

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: कोकरोच जनता पार्टी 5 सितंबर को दिल्ली में विरोध मार्च निकालेगी। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं से किए गए वादे पूरे नहीं किए। छात्रों पर दर्ज मामलों खत्म करने का आश्वासन भी पूरा नहीं हुआ है। पार्टी की कार्यसमिति की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। मार्च इंडिया गेट से शुरू होकर नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक जाएगा। इसमें नीट पेपर लोक के बाद आलाहत्या करने वाले छात्रों के परिजन भी शामिल होंगे। उसके धैर्य को कमजोरी नहीं समझा जाए।

होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेगा ईरान, संसद की मंजूरी

तेहरान, एजेंसी: ईरान की संसद ने होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जिन देशों के जहाजों को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति होगी, उनसे समुद्री सेवाओं के बदले शुल्क लिया जाएगा। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रवक्ता हसन काशकवी के अनुसार, शुल्क के बदले जहाजों को सुरक्षा, बीमा और अन्य समुद्री सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा पर्यावरण संबंधी सेवाएं और विशेष परिस्थितियों में ईंधन उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है। शुल्क का



भुगतान ईरानी रियाल या ईरान की पसंद की किसी अन्य मुद्रा में किया जा सकेगा।

इस बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाने की बात कही है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ईरान की आय के प्रमुख स्रोतों को बंद करने के लिए अपनी

नईदुनिया

भोपाल संस्करण

भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

राजधानी... वन प्रबंधन आधुनिक तकनीक से जुड़ेगा वनकर्मियों ...

खेल... महिला हॉकी विश्व कप: ऑस्ट्रेलिया से गोलरहित ड्रा के

व्यापार... देश में चीनी का पर्याप्त भंडार, जल्द घट सकते ...

देश-विदेश... लोकतंत्र की ताकत से आम व्यक्ति भी ...

‘द कश्मीर फाइल ओपन’: कश्मीरी पंडित हत्याकांडों की फिर जांच शुरू

पैंतीस साल पहले वंधामा गांव में नौ महिलाओं और चार बच्चों समेत 23 कश्मीरी पंडितों की हुई थी निर्मम हत्या

नईदुनिया ब्यूरो, श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर राज्य जांच एजेंसी ने गांढरबल के वंधामा नरसंहार की 35 साल पुराने मामले की जांच दोबारा शुरू कर दी है। 1998 में वंधामा गांव में नौ महिलाओं और चार बच्चों समेत 23 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। एजेंसी ने इसके अलावा कश्मीरी पंडितों की हत्या से जुड़े कई दशकों पुराने मामलों की भी दोबारा जांच शुरू की है। सूत्रों के अनुसार, जांच एजेंसी इन

मामलों में शामिल आतंकियों और उनके सहयोगियों की भूमिका का पता लगाने का प्रयास कर रही है। कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। 25 जनवरी 1998 की रात हथियारबंद आतंकियों ने वंधामा गांव में कश्मीरी पंडित परिवारों के घरों में घुसकर 23 लोगों की हत्या कर दी थी। हमलावरों ने परिवारों के सदस्यों को एक जगह एकत्र कर गोशियां चलाई थीं। यह घटना



गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले हुई थी। लंबे समय तक इस मामले में किसी आरोपी को सजा नहीं मिली। जांच के दायरे में कश्मीरी पंडित नेता और वकील टीका

लाल टपलू की हत्या का मामला भी है। 13 सितंबर 1989 को श्रीनगर में उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के लिए जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों को जिम्मेदार बताया गया था। पूर्व न्यायाधीश नीलकंठ गंजू की हत्या की भी दोबारा जांच की जा रही है। 4 नवंबर 1989 को श्रीनगर में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गंजू ने आतंकी मकबूल भट को मृत्युदंड सुनाया था।

कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट की 1990 में हुई हत्या की जांच भी दोबारा शुरू की गई है। इस मामले में एजेंसी ने जून में 737 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था। इसके अलावा कश्मीरी पंडित लेखक सर्वानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र कौल की हत्या की जांच भी चल रही है। दोनों का 1990 में अपहरण किया गया था और बाद में उनके शव पेड़ से लटके मिले थे।

दिल्ली-एनसीआर में तेज बारिश से 25 उड़ानें रद्द, कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात

आफत की वर्षा, जमीन-हवा में ‘मुश्किलें’

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में सोमवार सुबह से तेज बारिश हो रही है। खराब मौसम के कारण दिल्ली हवाईअड्डे पर विमान सेवाएं प्रभावित हुईं। 15 उड़ानों को दूसरे स्थानों के लिए भेजा गया, जबकि 25 उड़ानें रद्द होने और 380 उड़ानों के देरी से चलने की जानकारी सामने आई है। उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ का असर बढ़ गया है। राज्य के 19 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रयागराज के दारामंज घाट स्थित श्मशान क्षेत्र में पानी भर गया है। इसके कारण सड़कों पर अंतिम संस्कार किए जाने की स्थिति बनी है। मध्यप्रदेश के जबलपुर, चंबल और नर्मदापुरम



संभाग में तेज बारिश हुई है। अशोकनगर में एक युवक बाइक समेत तेज बहाव में बह गया। प्रदेश के 22 जिलों में बारिश को

लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी बारिश के साथ बिजली गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। मुंगेली जिले में

पैदल जा रही एक महिला पर बिजली गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बिलासपुर में स्कूल से घर लौट

रहे तीन बच्चे घोंघा नदी के तेज बहाव में बह गए। दिल्ली-एनसीआर में लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी है। खराब मौसम का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा है। उड़ानों के मार्ग में बदलाव और देरी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर जलभराव और तेज बहाव के कारण आवागमन पर असर पड़ा है। लगातार बारिश के बीच बाढ़ और बिजली गिरने की घटनाओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है।

दिल्ली से पटना जा रही 164 यात्रियों वाली पलाइट से टकराया पक्षी

पटना। पटना एयरपोर्ट पर सोमवार को दिल्ली से पटना आ रही एयर इंडिया की पलाइट लैंडिंग के दौरान बर्ड हिट का शिकार हो गई। विमान में 164 यात्री सवार थे। पायलट ने विमान को सुरक्षित रनवे पर उतारा, जिससे सभी यात्री सुरक्षित रहे। घटना के बाद एयरपोर्ट अधिकारियों और तकनीकी टीम को अलर्ट किया गया तथा विमान की जांच की गई। पटना एयरपोर्ट पर सात दिनों के भीतर बर्ड हिट की यह दूसरी घटना बताई जा रही है। लगातार ऐसी घटनाओं के सामने आने से एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों की मौजूदगी और उन्हें नियंत्रित करने की व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। विमानन क्षेत्र में बर्ड स्ट्राइक को गंभीर सुरक्षा चुनौती माना जाता है। लैंडिंग या उड़ान के दौरान पक्षियों के विमान से टकराने पर इंजन, पंख और अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में एयरपोर्ट प्रशासन के सामने पक्षियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है।



केंद्रीय संस्थानों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा- प्रदेश के विकास में संस्थानों की भागीदारी जरूरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान समय में कौशल नई मुद्रा और नवाचार नई अर्थव्यवस्था है। मध्यप्रदेश में प्रतिभाशाली युवा, प्राकृतिक संसाधन, कृषि शक्ति, उद्यमशीलता और औद्योगिक क्षमता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। आवश्यकता है कि इन संसाधनों का बेहतर उपयोग कर प्रदेश को ज्ञान और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाया जाए।

मुख्यमंत्री सोमवार को भोपाल में ‘समुद्र मध्यप्रदेश 2047’ के लिए केंद्रीय संस्थानों की भागीदारी पर आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र



मोदी ने देश को उसकी क्षमता का परिचय कराया है। संस्थानों को कौशल, शोध, नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय संस्थानों में उपलब्ध ज्ञान और

तकनीक का लाभ प्रयोगशालाओं और परिसरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ‘एक संस्थान-एक संकल्प’ मध्यप्रदेश के भविष्य

निर्माण की कार्ययोजना है। प्रत्येक संस्थान प्रदेश के विकास से जुड़ा ऐसा व्यावहारिक संकल्प ले, जिसे निर्धारित समय-सीमा में धरातल पर उतारा जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्रीय और राज्य स्तरीय संस्थान कौशल विकास, अनुसंधान, डिजिटल तकनीक, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण और उद्योग के क्षेत्रों में मिलकर कार्य करें। इससे रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्य सचिव अशोक बंगवाल ने कहा कि विकसित मध्यप्रदेश की जिम्मेदारी केवल शासन की नहीं, बल्कि सभी की है। युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियों के लिए कौशल संपन्न बनाना होगा।

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: मुंबई में ऑटो-रिक्शा चालकों ने मराठी बोलने से जुड़े सरकारी नियम के विरोध में सोमवार से तीन दिन की हड़ताल शुरू की। गैर-मराठी भाषी चालकों का कहना है कि इस नियम से उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उम्रदराज चालकों ने कहा कि 55 से 60 वर्ष की उम्र में परिवार चलाने के साथ नई भाषा सीखना उनके लिए मुश्किल है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने 19 अगस्त को कहा था कि चालकों को पहले नोटिस देकर मराठी सीखने के लिए तीन महीने का समय दिया जाएगा। इसके बाद भी मराठी नहीं सीखने पर लाइसेंस और बैज निलंबित किए जा सकते हैं। राज्य सरकार ने 20 अगस्त से



मराठी नहीं बोलने वाले ऑटो और टैक्सी चालकों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। चालकों ने सरकार से ज़ुर्माना लगाने के बजाय भाषा सीखने के लिए पर्याप्त समय देने की मांग की है। कई चालक मराठी सीखने और टूटी-फूटी मराठी बोलने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों की ओर से

नियम पूरा करने का समय देने के बजाय ज़ुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 15 से 20 हजार रुपये का ज़ुर्माना भरना उनके लिए मुश्किल है। परिवहन विभाग के अनुसार, 20 अगस्त से मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों में करीब 13 हजार चालकों की जांच की जा चुकी है।

फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- शादी बराबरी का रिश्ता...

मायके जाने पत्नी को किसी से अनुमति की जरूरत नहीं

▶▶ **पत्नी को ससुराल के काम और सास-ससुर की देखभाल के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता**

नईदुनिया ब्यूरो, बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी महिला को अपने मायके जाने के लिए पति या ससुराल के किसी सदस्य से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पति अपनी पत्नी को अपने माता-पिता की देखभाल करने या घर के काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि शादी किसी व्यक्ति को दूसरे की पहचान, स्वतंत्रता और इच्छा को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं देती। यह टिप्पणी तुमकुरु फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान की गई। मामले की सुनवाई जस्टिस डॉ. चिल्लाकुर सुमलता की पीठ ने की। फैमिली कोर्ट ने संबंधित व्यक्ति को पत्नी और नावालिग बेटी को हर महीने नौ हजार रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट ने कहा कि माता-पिता की देखभाल करना बेटे और बेटी का कर्तव्य है। दामाद या बहू को इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि घर के काम भी पुरुष और महिला के



बीच बराबर बांटे जाने चाहिए। याचिकाकर्ता पति ने दावा किया था कि उसकी पत्नी घर का काम नहीं करती थी और अपने सास-ससुर की देखभाल भी नहीं करती थी। इस पर अदालत ने कहा कि पत्नी की पारिवारिक जिम्मेदारियों को उसकी आज्ञाकारिता या दबकर रहने के

आधार पर नहीं आंका जा सकता। अदालत ने कहा कि पत्नी को अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीने के लिए दबाव में नहीं डाला जा सकता। केवल महिला होने के आधार पर उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगाया उसके अधिकारों के खिलाफ है। अदालत ने यह भी कहा कि महिला अपनी

इच्छा से अपने माता-पिता के घर जा सकती है और इसके लिए उसे ससुराल में मौजूद अन्य लोगों की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

हाईकोर्ट ने तुमकुरु फैमिली कोर्ट के नौ हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने के आदेश को बरकरार रखा। इसमें पत्नी के लिए पांच हजार रुपये और नावालिग बेटी के लिए चार हजार रुपये शामिल हैं। अदालत ने कहा कि महंगाई को देखते हुए यह राशि भी पर्याप्त नहीं है। पति इसी राशि को कम कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचा था। अदालत ने आदेश में बदलाव या उसे रद्द करने का कोई आधार नहीं माना।